

महिला क्षैतजि आरक्षण के अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार, राज्यपाल की मंजूरी के बाद होगा लागू

चर्चा में क्यों?

27 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के कार्मिक एवं सत्रकता सचिव शैलेश बगौली ने मीडिया को बताया कि राज्य की महिलाओं के क्षैतजि आरक्षण के लिये अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अगले हफ्ते ड्राफ्ट वधायी वभिग को भेजा जाएगा, वहाँ से राज्यपाल की मंजूरी के लिये राजभवन भेजा जाएगा।

प्रमुख बदि

- सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतजि आरक्षण देने के लिये अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में महिला क्षैतजि आरक्षण का कानून बन जाएगा।
- वदिति है कि नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा महिला क्षैतजि आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया। क्षैतजि आरक्षण बहाल कराने के लिये पछिले दनियों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश लाने पर सहमति बनी थी।
- शैलेश बगौली के मुताबकि प्रदेश सरकार की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतजि आरक्षण बहाल कराने के लिये भी शासन स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। इस संबंध में न्याय वभिग से वचिर-वमिर्श चल रहा है। क्षैतजि आरक्षण के समर्थन में ठोस वधिकि आधार तैयार करने के बाद प्रस्ताव न्याय वभिग को भेजा जाएगा।
- गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतजि आरक्षण के शासनादेश को नरिस्त कर दिया था।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सहि धामी के अनुरोध पर राज्यपाल लेख जख गुरमीत सहि (सेनखि) ने राजभवन में कई वर्षों से लंबति राज्य आंदोलनकारी क्षैतजि आरक्षण वधियक को लौटा दिया। इस वधियक के लौटने के बाद सरकार से क्षैतजि आरक्षण के लिये तात्कालिक तौर पर अध्यादेश या वधियक लाने की मांग की गई।